भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-390
बुधवार, 06 फरवरी, 2019/17 माघ, 1940 (शक)

औपचारिक रोजगार वृद्धि की घटती दर

390. श्री अहमद हसनः

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में औपचारिक रोजगार वृद्धि दर में गिरावट आई है;
(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान औपचारिक रोजगार वृद्धि दर को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (ग): श्रम ब्यूरो, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा रोजगार एवं बेरोजगारी पर आयोजित किए गए उपलब्ध श्रम बल सर्वेक्षणों के परिणामों के अनुसार, 15 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के व्यक्तियों हेतु सामान्य प्रमुख एवं सहायक स्थिति (यूपीएसएस) दृष्टिकोण पर आधारित कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) का अनुमान 2012-13 में 51.0%, 2013-14 में 53.7% एवं 2015-16 में 50.5% था।

श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा रोजगार सृजन को बढ़ावा देने हेतु नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए प्रधान मंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (पीएमआरपीवाई) आरंभ की गई है। इस योजना के तहत, सरकार सभी क्षेत्रों के समस्त पात्र नए कर्मचारियों हेतु तीन वर्षों के लिए ईपीएफ एवं ईपीएस के नियोक्ता के संपूर्ण अंशदान (12% अथवा यथा-स्वीकार्य) का भुगतान कर रही है। 28.01.2019 तक, इस योजना के अंतर्गत 1.30 लाख प्रतिष्ठानों के माध्यम से 1.05 करोड़ कर्मचारियों को लाभांवित किया गया है।

नियोजनीयता में सुधार करते हुए रोजगार का सृजन करना सरकार की प्राथमिकता रही है। सरकार इस दिशा में विभिन्न कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कर रही है जैसे पर्याप्त निवेश वाली विभिन्न परियोजनाओं को गति प्रदान करने और प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) तथा दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) जैसी योजनाओं पर सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करना।

*****